

**शव वाहन की आड़ में दूसरे संस्था की पर्ची काट
दहे श्रीराम धर्मर्थ अस्पताल से जुड़े लोग**

सुकृत सेवा मंडल का नाम आया सामने, रसीद पर फोन नंबर अस्पताल का निकला

मजदूर मोर्चा व्यूरो

फरीदाबाद: श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल की कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक घोटाले की कहानी खत्म होती है तो फैरैन दूसरा घोटाला सामने आ जाता है। श्रीराम के नाम पर चलने वाले इस अस्पताल में अब अर्धम का सहारा लेकर कमाई की जा रही है। जिसके तथ्यात्मक सबूत मिले हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई धार्मिक या सामाजिक संस्था शव बाहन के नाम पर भी कमाई कर सकती है। हालांकि कोरोनाकाल में जब तमाम संगठनों, संस्थाओं, निजी अस्पतालों ने अपने जमीर बेच दिए तो फरीदाबाद का पंजाबी समाज किस पर भरोसा करे। लेकिन श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल चलाने वाले इतनी निचली हक्रत पर उत्तरोंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं होगा।

शव वाहन की पर्ची से कमाई

शब्द वाहन की पर्ची से कमाई और इसके लिए निकाली गई तरकीब हैरान करने वाली है। श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल का शब्द वाहन एनआईटी में अक्सर चलता हुआ नजर आता है। यह शब्द वाहन श्रीराम अस्पताल की प्रॉपर्टी है। इस कन्फ्यूज़ियलाल खत्री की याद में समर्पित किया गया है। सेक्टर 55 में पिछले महीने एक मरीज की मौत हो गई। उसके परिवार ने श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल से शब्द वाहन की मांग की। श्रीराम अस्पताल का शब्द वाहन फौरन सेक्टर 55 पहुंचा और मरीज के शब्द को श्मशान घाट पहुंचा दिया। मरीज के परिवार



के नाम पर ही दी जानी चाहिए और उसके पैसे भी श्रीराम अस्पताल के पास आना चाहिए। शब वाहन को खत्री परिवार ने श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल को भेंट किया, क्योंकि शब वाहन पर कंवल खत्री के भाई स्व. कन्हैया लाल खत्री का नाम है। लेकिन किसी संस्था को भेंट करने के बाद आप उसके मालिक नहीं रहते, वो चीज़ संस्था की हो जाती है। लेकिन यहां तो कंवल खत्री ने भाई के नाम पर दान का नाम भी किया हुआ है और शब वाहन सेवा के नाम पर पैसे लेकर पर्ची सुकृत सेवा मंडल की काटी जा रही है। यह बहुत बड़ा फ़ॉड है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सुकृत सेवा मंडल की पर्चियों की आड़ में और भी गैर कानूनी कमाई की

ने बताया कि पीर जगन्नाथ ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि पिछले साल 20 जून को श्रीराम धर्मार्थ चेरिटेबल सोसायटी के दोनों पक्षों ने संस्था की चाबियां मेरे हवाले कर दी थीं। जो अभी भी मेरे पास सुरक्षित हैं। मैंने वो चाबी अभी तक किसी को नहीं दी है। हालांकि रजिस्टर सोसायटी के प्रशासक ने मुझसे चाबियां मार्गी थीं लेकिन दोनों पक्षों की सहमति न होने के कारण मैंने वो चाबियां प्रशासक को भी नहीं दीं।

पुलिस ने इस संबंध में कंवल खत्री का बयान भी लिया है। सूत्रों ने बताया कि कंवल खत्री ने पुलिस को दिए अपने बयान में खुद को पूर्व प्रधान बताया है। संस्था के उप प्रधान विशाल भाटिया की अस्पताल को कोविड सेंटर में बदलने की अर्जी के बाद कंवल खत्री ने प्रशासन को जो अर्जी दी थी, उसमें खुद को प्रधान नहीं लिखा था। लेकिन एमसीएफ के अतिरिक्त निगमायुक्त इंजीनियर कुलदीप्या ने श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल को कोविड सेंटर के लिए खोले जाने के संबंध में जो सरकारी पत्र जारी किया है, उसमें कंवल खत्री को प्रधान लिखा गया है। इस तरह यह स्थिति अब पूरी तरह साफ हो गई है कि एमसीएफ ने अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर कंवल खत्री को प्रधान लिखा और उसके लिए अस्पताल में घुसने का रास्ता साफ किया। यह मामला आगे चलकर अदालत में एमसीएफ के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है।

सूत्रों ने बताया कि रजिस्टर सोसायटी के प्रशासक संघपाल ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि कोविड की वजह से अस्पताल को खोला गया। मेरे पास इस चीज की पावर रजिस्टर सोसायटी की तरफ से है कि मैं बंद अस्पताल को खुलवा सकता हूँ। लेकिन यहाँ सबाल यह उठ रहा है कि जिन चारियों को पुलिस ने अपने सामने पीर जगत्राथ के पास पिछले साल रखवाई थीं, कोई प्रशासक बिना उन चारियों के दुप्लीकेट चारी बनवाकर अस्पताल कैसे खुलवा सकता है। प्रशासक के अधिकार सोसायटी एक्ट में तय हैं। इस मामले में अब प्रशासक के अधिकारों का सच भी जल्द ही सामने आएगा।

बता देंगे कि पिछले साल दोनों पक्षों में विवाद होने के बाद पुलिस आई थी और पुलिस के सामने ही वो चाबियां पीर जगत्राथ को सौंपने का फैसला दोनों पक्षों ने किया था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कांडिड सेंटर खोलने के लिए एक पक्ष कहीं अस्पताल में जबरन तो नहीं भया।

मुख्यमंत्री से क्यों मिलवाया सीमा ने जबन ता नहीं दुसरा।
भाजपा विधायक सीमा त्रिखा हाल ही में शहर के कुछ व्यापारी नेताओं को खट्टर से मिलवाने ले गई थीं। उस प्रतिनिधिमंडल में कवल खत्री और जगिन्द्र चावला भी थे। फोटो खंचने के समय विधायक सीमा त्रिखा ने अपने साथ ही कंवल खत्री और जगिन्द्र चावला को खड़ा किया। इस मुलाकात की खबर हमारे देखीं-सुनी कॉलम में भी पढ़ें। दरअसल, इस मुलाकात और फोटो के जरिए फरीदाबाद के अफसरों को संकेत देने की काशिश की गई है कि इन दोनों को भाजपा विधायक का संरक्षण प्राप्त है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हरियाणा सरकार श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल को अवैध

निर्माण मानती है और इसी आधार पर एमसीएफ ने इसे सील कर दिया था। अब सवाल यह है कि एक भाजपा विधायक अवैध कब्जाधारियों को सीएम से मिलवाकर क्या साबित करना चाहता है। एमसीएफ कंवल खत्री से तिकोना पार्क की इस जमीन की लीज के कागजात मांग चुका है लेकिन कंवल खत्री उन कागजात के एमसीएफ में पेश नहीं कर सके। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि श्रीराम अस्पताल का काविड सेंटर नाकाम साबित होने के बाद अब यहां ओपीडी की अनुमति देने के लिए विधायकों की ज़रूरत है।

लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन प्रशासन यह समझ नहीं पा रहा है कि रजिस्ट्रार सोसायटीज फरीदाबाद और स्टेट रजिस्ट्रार सोसायटी चंडीगढ़ में श्रीराम धर्मार्थ का केंस लंबित होने की वजह से वे यहाँ पर ओपीडी चलाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। भाजपा विधायक ने अधिकारियों से कहा है कि वे किसी भी तरह इस समस्या का हल निकालें। सुन्दरी ने बताया कि सीमा त्रिखा ने इस संबंध में आरएसएस के पदाधिकारी गंगाशंकर के साथ बैठक भी रखी थी, जिसमें यहाँ ओपीडी चलावाने के लिए आरएसएस के रसखां भी इस्तेमाल करने की रणनीति पर चर्चा हुई। बताया जाता है कि कंवल खरी ने इन लोगों को आश्वस्त किया है कि काहे जितना पैसा खर्च हो जाए, यहाँ ओपीडी चलावा दी जाए।

देखी-सुनी

खबरीलाल

मीडिया कोऑर्डिनेटरों के भरोसे खदूर

आखिर खट्टर सरकार को अपने लिए कितने मीडिया सलाहकार चाहिए? मुख्यमंत्री के चार मीडिया सलाहकारों के बाद अब खट्टर सरकार ने सीएम की मदद के लिए पाँच मीडिया कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त कर दिए हैं। हर ज़िले में डीपीआरओ पहले से ही है। चंडीगढ़ और दिल्ली में लोकसंपर्क विभाग का एक बहुत बड़ा अमला अलग से है। आप समझ सकते हैं कि खट्टर सरकार किस तरह मीडिया सलाहकारों पर आश्रित होती जा रही है। ये जो पाँच मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, उनकी सैलरी, दफ्तर, स्टाफ कहाँ से आएगा? ज़ाहिर है जनता के टैक्स का पैसा इन पर खर्च होगा। अगर प्रदेश के डीपीआरओ और पूरा लोक संपर्क विभाग खट्टर सरकार का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस विभाग को बंद करके सारी कामान मीडिया सलाहकारों और मीडिया कोऑर्डिनेटरों को साँप दी जाए। फरीदाबाद के लिए मुकेश वशिष्ठ को सीएम का मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। आखिरकार वह भी तो सीएम की पब्लिसिटी के लिए अखबारों और टीवी पर निर्भर रहेंगे। यहां काम डीपीआरओ का भी है। सरकार ने मीडिया कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति करते हुए यह नहीं बताया है कि वे राज्य के विभिन्न शहरों में बैठकर क्या घास खोदेंगे।... लगता है कि खट्टर सरकार गलतफहमी की शिकार है कि वो मीडिया सलाहकारों और मीडिया कोऑर्डिनेटरों के भरोसे जनता में अपनी छवि बदल लेगी या मजदूर मोर्चा जैसे निष्पक्ष अखबार सरकार को आईना दिखाने का काम बद कर देंगे।

चोला और पाला बदलते व्यापारी नेता



दिखे। बड़खल की भाजपा विधायक सीमा त्रिखा कुछ व्यापारी नेताओं को बटोर कर दिल्ली में हरियाणा भवन खट्टर से मिलाने ले गई, ताकि खट्टर का धन्यवाद किया जा सके। इस प्रतिनिधिमंडल में बहुत सरे व्यापारी नेता थे जो पहले खट्टर और मोदी को उल्टा सीधा बोलते रहे हैं। वकील जोगिन्द्र चावला भी व्यापारियों के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे। जबकि जोगिन्द्र चावला का बाकायदा एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो खट्टर और मोदी को गलत बोलते दिख रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में जगदीश भाटिया भी थे जो पूर्व भाजपा विधायक स्व कुंदन लाल भाटिया के पुत्र हैं। आजकल एक मंदिर की गद्दी संभाल रहे हैं लेकिन व्यापारी नेता बनकर खट्टर दखारा में पहुंचे। जगदीश भाटिया भी खट्टर सरकार के कटु आलोचक रहे हैं। उनके बाई चन्द्र भाटिया ने भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ चुके हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में जोगिन्द्र चावला के साथ श्रीराम धर्मार्थ चेरिटेबल सोसायटी के निलंबित प्रधान कंवल खत्री भी थे। इन कथित व्यापारी नेताओं के ड्राइवरों तक को इस प्रतिनिधिमंडल में शमिल किया गया था।...अब बाकी व्यापारी नेताओं के बारे में क्या बताएं। समझा जाता है कि सरकार की गिरती जा रही लोकप्रियता को बचाने के लिए भाजपा आला कमन ने सीमा त्रिखा जैसे विधायकों को इस टोटके को अंजाम देने के लिए लगाया है। शहरी क्षेत्रों में धोरे-धोरे व्यापारी कंग्रेस की तरफ मुड़ रहे हैं, खासकर पंजाबी बिरादरी के व्यापरियों का रुक्न बदल रहा है।

प्रेस कॉन्फ्रेस में तारीफों के पुल

डीसी फरीदाबाद यशपाल यादव ने 2 जून को आनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय पहले से तय नहीं था तो जाहिर है डीसी ने अपनी उपलब्धियों के बारे में पत्रकारों को आनलाइन आमंत्रित किया था। लेकिन डीसी से सवाल पूछने वाले पत्रकार भाई डीसी की तारीफ भी करते नहीं थे। किसी ने उनके ट्रेनिंग से फौरन आकर चार्ज संभालने को याद दिलाया तो किसी पत्रकार ने कहा कि उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से कोरोना काल में शहर और गांव के हालात संभाले। डीसी मुस्कुरा कर मुनते रहे। तारीफ किसे पसंद नहीं आती। किसी पत्रकार ने डीसी को घेरने वाले सवालों की बौछार नहीं की। प्राइवेट अस्पतालों की लूट की बात पत्रकारों ने उठाई लेकिन वह नहीं पूछ सके कि किसी बड़े अस्पताल पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। डीसी का इस सवाल पर जवाब यही होता न कि अभी जांच करा रहे हैं। तो फिर बलभगाड़ में जिस प्राइवेट अस्पताल पर कार्रवाई का ढिंडोरा पीटा गया तो वह क्या था, क्या उसी तरह की गड़बड़ी एशियन अस्पताल, मेट्रो अस्पताल, फोर्टिस और सर्वोदय नहीं कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। बेशक आप सांकेतिक कार्रवाई ही करते लेकिन लूट के इन बड़े अड्डों पर भी कार्रवाई तो बनती है।

फरीदाबाद से चंडीगढ़ तक एक कैलेंडर की चर्चा



फरीदाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक के सरकारी क्षेत्रों में एक कैलेंडर की इन दिनों बहुत चर्चा है। हाल ही में एक अधिकारी ने खबरिलाल को जब यह कैलेंडर दिखाया तो खबरिलाल भी दंग रह गया। मजदूर मोर्चा ने बहुत पहले एनआईटी इलाके में नारंग परिवार के सरकारी संपत्तियों पर लूट-खसोट की खबर प्रकाशित की थी। इस कैलेंडर में उसी नारंग परिवार पर हमला किया गया है। किसी मुद्दे को उठाने की यह तरकीब बहुत जबरदस्त है। फरीदाबाद के कई सरकारी दफतरों और शहर के कारोबारियों के यहां इस कैलेंडर के दर्शन हुए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट और समाजसेवी रमेश छाबड़ा की तरफ से निकाले गए इस कैलेंडर एक तरफ तो खट्टर सरकार की तारीफों के पुल बांधे गए हैं तो दूसरी तरफ उनसे पूछा गया है कि इत्तीन ईमानदार सरकार नारंग परिवार की लूट-खसोट पर चुप क्यों हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस कैलेंडर पर वो संज्ञान भी लें तो किस चीज का। हालांकि इसमें तमाम आरोप लगाए गए हैं। कैलेंडर के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, अलबत्ता इसे जारी करने वाले ने नारंग परिवार की इज्जत को धो डाला है।